

प्रारंभिक परीक्षा

ज्ञान भारतम मिशन

संदर्भ

ज्ञान भारतम सर्वेक्षण ने पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों (manuscripts) का मानचित्रण किया है।

ज्ञान भारतम मिशन के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन।
- **फोकस:** भारत की पांडुलिपि विरासत का डिजिटल संरक्षण, सूचीकरण (cataloguing) और साझाकरण।
- **शामिल पांडुलिपियां:** इसमें संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में ताड़ के पत्ते (palm-leaf), भोजपत्र (birch bark) और कागज की पांडुलिपियां शामिल हैं।

पांडुलिपि क्या है?

- ताड़ के पत्ते, भोजपत्र, कपड़े, कागज या धातु जैसी सामग्री पर हस्तलिखित रचना — जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी हो और जिसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या सौंदर्यशास्त्रीय मूल्य हो।
- मुद्रित पुस्तकों या प्रशासनिक रिकॉर्ड के विपरीत, पांडुलिपियों में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य और कला से जुड़े ज्ञान की विषयवस्तु समाहित होती है।
- यह सैकड़ों भाषाओं और लिपियों में पाई जाती हैं; एक ही भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है (जैसे, देवनागरी, उड़िया और ग्रंथ लिपि में संस्कृत)।
- भारत की पांडुलिपि संपदा का अनुमान 50 लाख से अधिक कृतियों का है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

संदर्भ

PMSMA ने 2026 में अपने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

PMSMA के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से कार्यान्विता।
- **उद्देश्य:** प्रारंभिक जोखिम की पहचान और समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से सुरक्षित गर्भधारण सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care) प्रदान करना।
- **विशेषताएँ:**

- **लाभार्थी:** दूसरी और तीसरी तिमाही (2nd & 3rd trimesters) की गर्भवती महिलाएँ; उच्च जोखिम वाले मामलों और ड्रॉपआउट को प्राथमिकता।
- **अनुसूची:** प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में।
- **चिकित्सक स्वयंसेवक प्रणाली:** निजी चिकित्सक 9 तारीख को स्वेच्छा से अपनी सेवा देते हैं; उन्हें 'IPledgeFor9' अचीवर्स अवार्ड्स के माध्यम से मान्यता दी जाती है।
- **सेवा:** इसमें नैदानिक परीक्षण, प्रयोगशाला जांच (रक्त/मूत्र परीक्षण), अल्ट्रासोनोग्राफी, दवाएं, और पोषण तथा जन्म योजना (birth planning) पर परामर्श शामिल हैं।
- **विस्तारित PMSMA रणनीति (2022):** यह लाभार्थियों और आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और SMS अलर्ट प्रणाली के समर्थन के साथ, सुरक्षित प्रसव तक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए अनुवर्ती देखभाल (follow-up care) को मजबूत करती है।
- **प्रभाव एवं उपलब्धियाँ:**
 - 7.50 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व सेवाएं प्रदान की गई हैं।
 - मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 130 (2014-16) से घटकर 87 प्रति लाख जीवित जन्म (2022-24) हो गया है।

संबद्ध मातृ स्वास्थ्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence)

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** संस्थागत प्रसव (institutional deliveries) को बढ़ावा देती है; 2014-15 से 11.96 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है; इसके 18.05 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं।
- **सुमन (SUMAN), पोषण अभियान, पीएमएमवीवाई (PMMVY) और लक्ष्य (LaQshya):** ये योजनाएं सामूहिक रूप से पोषण, मातृत्व लाभ और लेबर रूम की गुणवत्ता को संबोधित करती हैं।

बॉन जलवायु वार्ता में भारत

संदर्भ

जर्मनी के बॉन में चल रहे UNFCCC सहायक निकायों के 64वें सत्र (SB64) में भारत ने प्रमुख हस्तक्षेप किए।

UNFCCC सहायक निकायों के बारे में

- UNFCCC दो स्थायी सहायक निकायों के माध्यम से कार्य करता है जो COP (पार्टियों के सम्मेलन) के बीच तकनीकी और प्रक्रियात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करते हैं:
 - **SBI (कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय):** यह UNFCCC प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और राष्ट्रीय संचार की समीक्षा करता है।
 - **SBSTA (वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय):** यह वैज्ञानिक निष्कर्षों और नीति के बीच सेतु का काम करता है, जो तकनीकी मामलों पर COP को सलाह देता है।

- उनका मध्य-वर्षीय बॉन सत्र (SB64) वार्षिक COP में अंगीकरण के लिए मसौदा निर्णय तैयार करता है; यहाँ के परिणाम COP31 से पहले वार्ता योग्य पाठ (negotiable text) बन जाते हैं।
- **अगला COP:** COP31 की मेजबानी अंताल्या, तुर्किये (नवंबर 2026) में की जाएगी; वार्ता की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया कर रहा है।

भारत का प्रमुख रुख

- सिकुड़ते जलवायु वित्त पूल और चौड़ी होती अनुकूलन वित्त खाई (adaptation finance gap) से निपटने का आह्वान किया।
- विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तपोषित करने के पेरिस समझौते के प्रावधान के लिए समर्पित एजेंडा स्थान (agenda space) का आग्रह किया।
- एकतरफा व्यापार उपायों (जैसे, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र — CBAM) और UNFCCC कन्वेंशन के अनुच्छेद 3.5 के तहत विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई पर उनके प्रतिकूल प्रभावों पर संवाद के लिए दबाव डाला।
- शमन कार्य कार्यक्रम (Mitigation Work Programme) को निर्देशात्मक (prescriptive) बनाने के खिलाफ आगाह किया; और आग्रह किया कि यह अपने सुविधाजनक स्वरूप (facilitative character) को बनाए रखे।

शमन कार्य कार्यक्रम (MWP) या शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम

- COP26 में स्थापित, और COP27 में शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य वर्तमान प्रक्षेप पथों और 1.5°C पेरिस समझौते के लक्ष्य के बीच की खाई को पाटने में मदद करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी को तत्काल बढ़ाना है।
- यह एक सुविधाजनक, गैर-निर्देशात्मक मंच के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रों पर नए दायित्व थोपे बिना समाधान, सर्वोत्तम प्रथाओं और निवेश के अवसरों को साझा करता है।
- यह चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy), ऊर्जा, अपशिष्ट और परिवहन जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए सालाना कम से कम दो वैश्विक संवाद और निवेश-केंद्रित कार्यक्रमों को अनिवार्य करता है।

सैजिटेरियस ए (SAGITTARIUS A)

संदर्भ

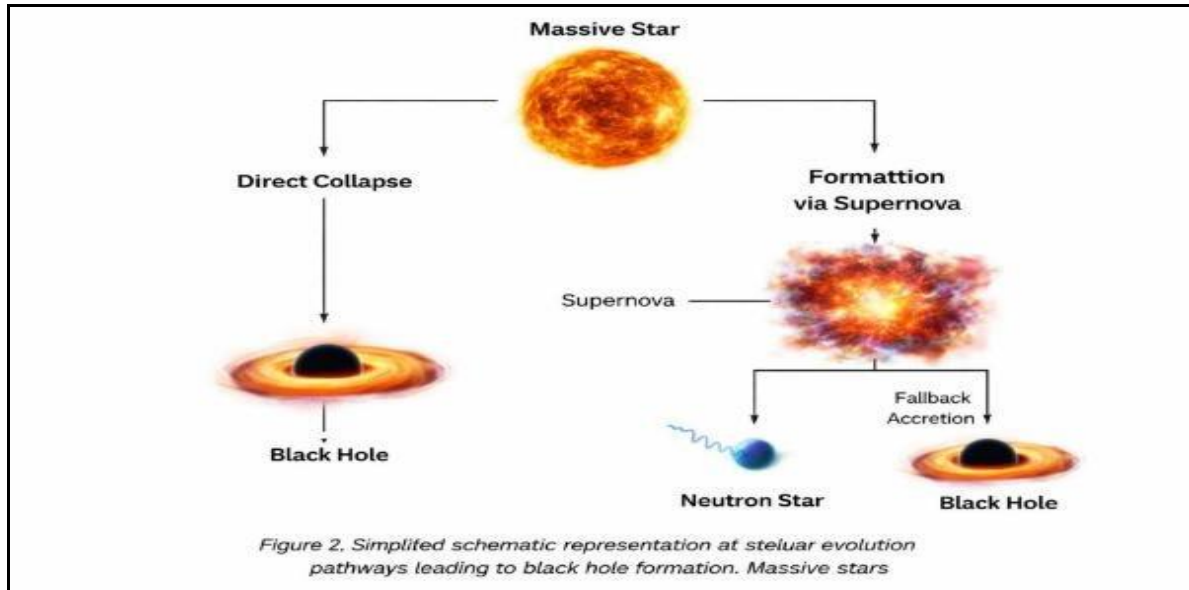
ALMA टेलीस्कोप (चिली) का उपयोग करने वाले एक नए अध्ययन ने सैजिटेरियस ए* से बहने वाली एक सक्रिय हवा (active wind) का पहला निश्चित प्रमाण प्रदान किया है।

मुख्य निष्कर्ष

- **हवा का निर्माण:** ब्लैक होल के पास घूमने वाली गैस गर्म होकर अति-तप्त प्लाज्मा (superhot plasma) में बदल जाती है, जिसका केवल 1 ग्राम आसपास की 100 किलोग्राम गैस को दूर धकेल सकता है, जिससे यह हवा बनती है।

- **महत्व:** यह हवा तारों के निर्माण को नियंत्रित करती है, और भगोड़े सुपरनोवा (runaway supernovae) को आकाशगंगा के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक गैस को नष्ट करने से रोकती है।

- **सैजिटेरियस ए (Sgr A):** यह मिल्की वे (आकाशगंगा) के गैलेक्टिक केंद्र (Galactic Center) पर स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है।
 - यह पृथ्वी से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर सैजिटेरियस (धनु) तारामंडल की दिशा में स्थित है, और यह हमारे सूर्य से लगभग 43 लाख गुना अधिक विशाल है।
- **ALMA (अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर एरे):** यह अटाकामा रेगिस्तान, चिली में स्थित एक उच्च-सटीक रेडियो टेलीस्कोप एरे है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष में ठंडी गैस, धूल और आणविक बादलों (molecular clouds) का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है।



एफसीएनआर (बी) [FCNR(B)] डिपॉजिट

संदर्भ

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने सितंबर 2026 तक फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट बैंक (FCNR(B)) डिपॉजिट के लिए एक स्पेशल स्वैप स्कीम की घोषणा की, जिससे बैंकों को भारतीय बाजारों में नया विदेशी कैपिटल लाने की सुविधा मिलेगी।

FCNR(B) डिपॉजिट के बारे में

- इसे भारत में नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) और ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ़ इंडिया (OCI) खुलवा सकते हैं।
- इसे विदेशी मुद्राओं जैसे US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन और कैनेडियन डॉलर में रखा जाता है।

- इसमें रुपये की कीमत घटने (डिप्रीसिएशन) का कोई जोखिम नहीं होता है।
- जब तक जमाकर्ता भारतीय टैक्स कानूनों के तहत नॉन-रेसिडेंट की श्रेणी में आता है, तब तक जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज पर भारत में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।

स्वैप योजना के बारे में

- बैंक 3 से 5 साल की FCNR(B) जमा राशि जुटा सकते हैं और उन्हें RBI के साथ रियायती दर पर स्वैप कर सकते हैं, जिसमें हेजिंग की लागत (करेंसी की कीमत में उतार-चढ़ाव से होने वाला जोखिम) RBI उठाता है।
- इससे FCNR(B) जमा राशि उधार देने वालों के लिए विदेश से फंड जुटाने का एक ज़्यादा आकर्षक ज़रिया बन जाती है।
- इस स्कीम के ज़रिए RBI विदेशी पूंजी के तौर पर अतिरिक्त 70 अरब डॉलर जुटा सकता है।

1. **NRE (नॉन-रेसिडेंट एक्सटर्नल):** विदेशी आय को रुपये में बदलकर जमा किया जाता है; इसे विदेशी मुद्रा में नहीं रखा जा सकता।
2. **NRO (नॉन-रेसिडेंट ऑर्डिनरी):** रुपये में चलने वाला करंट/सेविंग्स अकाउंट; यह उन NRI के लिए सबसे अच्छा है जिनकी आय भारत के अंदर होती है (जैसे पेंशन, किराया)। इसमें विदेशी जमा राशि स्वीकार की जाती है, लेकिन उसे रुपये में बदल दिया जाता है।

चुनाव चिह्न

संदर्भ

व्यंग्यात्मक कॉकरोच जनता पार्टी (CJIP) द्वारा इस्तेमाल की गई कॉकरोच की छवि ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या कोई राजनीतिक दल कॉकरोच को अपने चुनाव चिह्न के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

चुनाव चिह्न कैसे आवंटित किए जाते हैं?

- यह चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 द्वारा शासित होता है।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव आयोग (EC) द्वारा आरक्षित चिह्न आवंटित किए जाते हैं - जैसे, भाजपा के लिए कमल, कांग्रेस के लिए हाथ।
- गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव आयोग के "मुक्त चिह्नों" (free symbols) की सूची से एक चिह्न का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पसंद का विकल्प मिलने का कोई आश्वासन नहीं होता है।

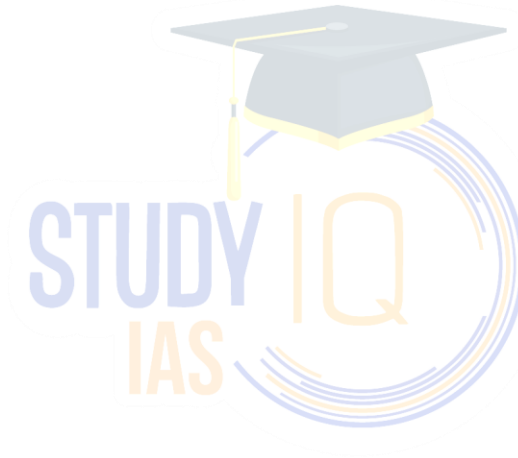
मुक्त सूची में कौन से चिह्न हैं?

- चुनाव आयोग मुक्त चिह्नों की एक सूची रखता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जिसमें फल, सब्जियां, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण और खेल उपकरण शामिल होते हैं।
 - नवीनतम सूची (मई 2025) में 184 चिह्न हैं।
- सेब जैसे कुछ चिह्नों को स्वतंत्र रूप से आवंटित किया जा सकता है, सिवाय अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जहाँ यह एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी के लिए आरक्षित है।

- दो अलग-अलग राज्यों में दो अलग-अलग मान्यता प्राप्त दल एक ही चुनाव चिह्न साझा कर सकते हैं; इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है, और उनके एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना भी नहीं होती है।

क्या कोई जीव (Creature) चुनाव चिह्न हो सकता है?

- 1990 के दशक में पशु कल्याण कार्यकर्ताओं के अभ्यावेदन (representations) के बाद, चुनाव आयोग ने चुनाव चिह्न के रूप में जानवरों को आवंटित करना बंद कर दिया था।
- विरासत वाले पशु चिह्न जो अभी भी बरकरार हैं उनमें हाथी (बहुजन समाज पार्टी - BSP, हालांकि असम में यह प्रतिबंधित है) और शेर (ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक) शामिल हैं।



मुख्य परीक्षा

भारत का प्रजनन परिवर्तन और आगे की राह

संदर्भ

भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) NFHS-6 (2023-24) में गिरकर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निहितार्थों के साथ एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन (demographic transition) का संकेत देता है।

गिरती प्रजनन दर का वैश्विक परिदृश्य कैसा दिखता है?

- **प्रजनन दर में तीव्र वैश्विक गिरावट:** संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाओं (UN World Population Prospects) के अनुसार, वैश्विक TFR 1960 में 4.68 से गिरकर 2024 में 2.18 हो गया है।

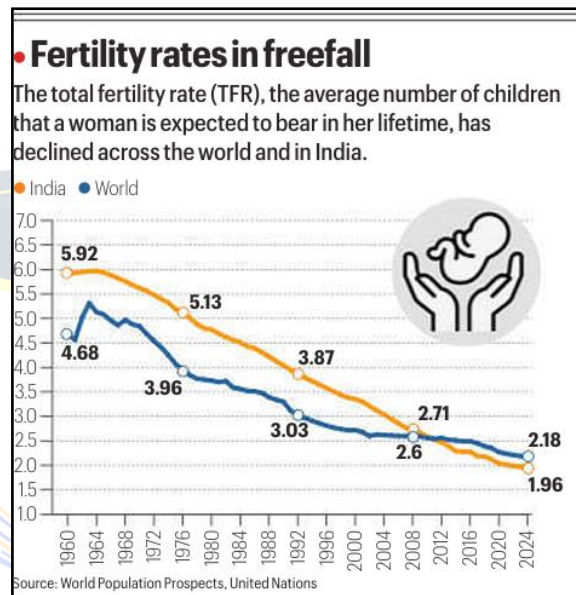
- **पूर्वी एशिया प्रजनन संकट के केंद्र में:** शहरी लागत के दबाव, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली और कमजोर पैतृक समर्थन बुनियादी ढांचे (parental support infrastructure) से प्रेरित।
 - उदा., दक्षिण कोरिया का TFR गिरकर 0.72 हो गया है - जो दुनिया में सबसे कम है।

- **उप-सहारा अफ्रीका एक जनसांख्यिकीय अपवाद (Outlier) के रूप में:** उप-सहारा अफ्रीका तेजी से वैश्विक जन्म संख्या पर हावी होगा, जो एक स्पष्ट "बेबी बूम बनाम बेबी बस्ट" भू-राजनीतिक विभाजन (geopolitical divide) पैदा करेगा।

- **दीर्घकालिक वैश्विक परिवर्तन:** लैंसेट (Lancet) के एक अनुमान के अनुसार, 2100 तक 204 देशों और क्षेत्रों में से 198 में प्रतिस्थापन-से-कम प्रजनन दर (below-replacement fertility) होने की उम्मीद है, जो यह दर्शाता है कि गिरती प्रजनन दर एक अस्थायी प्रवृत्ति के बजाय एक संरचनात्मक वैश्विक परिवर्तन है।

पूरे भारत में प्रजनन दर क्यों गिर रही है?

- **बढ़ती महिला शिक्षा और कार्यबल भागीदारी:** जैसे-जैसे महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और औपचारिक रोजगार में प्रवेश करती हैं, बच्चे पैदा करने की अवसर लागत (opportunity cost) बढ़ जाती है, जो सीधे तौर पर प्रजनन निर्णयों को कम करती है।
 - उदा., केरल और तमिलनाडु, जिनकी महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, क्रमशः 1.8 और 1.7 का TFR दर्ज करते हैं, जो भारत में सबसे कम में से हैं।



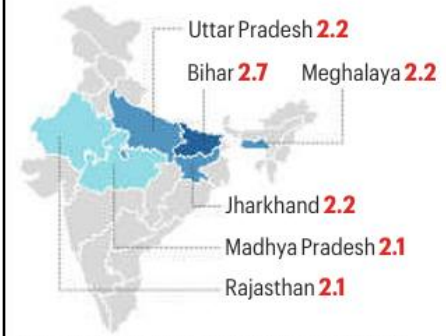
- **शहरीकरण और बच्चों के पालन-पोषण की बढ़ती लागत:** शहरी आवास लागत, निजी स्कूली शिक्षा शुल्क और प्रतिस्पर्धी पालन-पोषण मानदंड बच्चों को आर्थिक रूप से बोझिल बनाते हैं, जो बच्चों को आर्थिक संपत्ति मानने की पारंपरिक ग्रामीण सोच को उलट देता है।
- **गर्भनिरोधक का विस्तार और घटती बाल मृत्यु दर:** आय समूहों में आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग का काफी विस्तार हुआ है, जबकि गिरती शिशु मृत्यु दर ने बाल मृत्यु के खिलाफ बीमा के रूप में अतिरिक्त बच्चे पैदा करने के प्रोत्साहन को कम कर दिया है।
- **"वृद्धावस्था सुरक्षा" के उद्देश्य में गिरावट:** जैसे-जैसे पेंशन कवरेज का विस्तार होता है और वित्तीय साधनों का विकास होता है, ग्रामीण परिवार वृद्धावस्था के समर्थन के लिए विशेष रूप से बच्चों पर निर्भर नहीं होते हैं, जिससे ऐतिहासिक रूप से एक शक्तिशाली प्रजनन कारक कमजोर हो जाता है।
- **विलंबित विवाह:** 18 वर्ष से पहले विवाह करने वाली 20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत NFHS-5 के 23.3% से घटकर NFHS-6 में 16.7% हो गया है, जिससे प्रभावी प्रजनन अवधि (reproductive window) कम हो गई है।

भारत के लिए उप-प्रतिस्थापन प्रजनन दर के प्रमुख निहितार्थ क्या हैं?

- **क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन:** भारत की प्रजनन दर में गिरावट एक समान नहीं है; यह जनसांख्यिकीय रूप से उन्नत दक्षिणी राज्यों और अभी भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे उत्तरी राज्यों (जैसे यूपी, बिहार) के बीच एक चौड़ी होती आर्थिक और राजनीतिक दरार पैदा करती है।
- **संकुचित होता जनसांख्यिकीय लाभांश:** घटती प्रजनन दर धीरे-धीरे कामकाजी उम्र की आबादी की वृद्धि को कम कर देगी, जो आने वाले दशकों में भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को सीमित कर देगी।
- **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर राजकोषीय दबाव:** कार्यबल के सापेक्ष एक बड़ी बुजुर्ग आबादी पेंशन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और सामाजिक सुरक्षा खर्च पर दबाव बढ़ाएगी।
 - 2050 तक, भारत में बुजुर्ग व्यक्तियों का अनुपात जनसंख्या का 20.8% यानी लगभग 34.7 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **परिसीमन और संघीय तनाव:** जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के भविष्य के पुनर्वितरण से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, जिससे उत्तर-दक्षिण राजनीतिक बहस तेज हो सकती है।
- **प्रतिकूल लिंगानुपात का जोखिम:** जिन क्षेत्रों में पुत्र प्राप्ति की प्राथमिकता (son preference) बनी हुई है, वहां छोटे परिवार के आकार लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे लिंग संतुलन प्रभावित हो सकता है।

● In most states, fertility below replacement level

The map shows the only states with TFR at or above 'replacement level' (2.1 children per woman). This is the level needed to maintain a stable population



Source: National Family Health Survey (NFHS-6), 2023-24

जन्म-समर्थक (Pro-Natalist) नीतिगत हस्तक्षेपों से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

- **एक-समान प्रोत्साहन (One-Size-Fits-All Incentives) प्रतिकूल हैं:** आंध्र प्रदेश के तीसरे बच्चे के अनुदान (third-child grant) जैसे वित्तीय प्रोत्साहन इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि शहरी पेशेवर परिवारों बनाम गरीब ग्रामीण परिवारों में प्रजनन क्षमता में गिरावट के बहुत अलग संरचनात्मक कारक हैं।
- **दंडात्मक/बलपूर्वक निहितार्थ का जोखिम (Risk of Coercive Undertones):** प्रजनन मानदंडों को कल्याणकारी लाभों या चुनावी पात्रता से जोड़ने से गरीब, हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों पर असंगत प्रभाव पड़ सकता है।
 - उदा., आंध्र प्रदेश ने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने (2024 तक) से हटकर दो से कम बच्चों वालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव (2025) किया, जो प्रजनन व्यवहार को प्रभावित करने के लिए चुनावी कानूनों के उपयोग की विसंगति को उजागर करता है।
- **प्रजनन क्षमता को कानून द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता:** अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि शिक्षा, शहरीकरण और महिला सशक्तिकरण द्वारा संचालित प्रजनन दर में गिरावट को केवल नकद प्रोत्साहन या नियामक उपायों के माध्यम से उलटना मुश्किल है।

आगे की राह क्या है?

- **केवल प्रोत्साहनों में नहीं, सक्षम परिस्थितियों में निवेश करना:** कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चे पैदा करने की संरचनात्मक लागत को कम करने के लिए वहनीय (affordable) चाइल्डकैअर बुनियादी ढांचे, माता-पिता दोनों के लिए सवैतनिक अवकाश और लचीली कार्य व्यवस्था का विस्तार करना।
 - उदा., नॉर्डिक देश चाइल्डकैअर को निजी बोझ के बजाय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में मानकर अपेक्षाकृत उच्च TFR (~1.7-1.8) बनाए रखते हैं।
- **उत्पादकता और आंतरिक प्रवास के माध्यम से परिवर्तन का प्रबंधन करना:** प्रजनन क्षमता में गिरावट को उलटने का प्रयास करने के बजाय, भारत को भविष्य के छोटे कार्यबल के साथ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि को बनाए रखने के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लानी चाहिए, और श्रम-कमी वाले दक्षिणी राज्यों में उत्तरी श्रम अधिशेष को चैनलाइज करने के लिए एक संरचित आंतरिक प्रवासन नीति विकसित करनी चाहिए।
- **बुजुर्गों की देखभाल के बुनियादी ढांचे को अभी प्राथमिकता देना:** दक्षिण और पश्चिमी भारत में पहले से चल रहे जनसांख्यिकीय बदलाव की तैयारी के लिए जेरियाट्रिक (geriatric) स्वास्थ्य सेवा, पोर्टेबल पेंशन प्रणालियों और सामुदायिक देखभाल मॉडल में तुरंत निवेश करना।
 - उदा., सिंगापुर का एल्डरशील्ड (ElderShield) और जापान का लॉन्ग-टर्म केयर इंश्योरेंस एक्ट राज्य द्वारा वित्तपोषित बुजुर्ग सहायता प्रणालियों के लिए स्केलेबल मॉडल प्रदान करते हैं।
- **पुत्र प्राथमिकता को सक्रिय रूप से संबोधित करना:** उच्च पुत्र-प्राथमिकता वाले जिलों में सामुदायिक स्तर के व्यवहारिक हस्तक्षेपों के साथ 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को मजबूत करें ताकि प्रजनन दर में गिरावट को लिंग-चयनात्मक परिणामों को ट्रिगर करने और बाल लिंगानुपात में हुए लाभ को उलटने से रोका जा सके।

भारत-नेपाल संबंध एक अहम मोड़ पर

संदर्भ

नेपाल के प्रधानमंत्री की संसदीय स्वीकृति कि कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा विवाद में दोनों पक्षों के दावे शामिल हो सकते हैं, साथ ही 2025-26 के दौरान उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ताओं की श्रृंखला ने भारत-नेपाल संबंधों को रीसेट करने का एक नया अवसर खोल दिया है।

भारत-नेपाल संबंधों को विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण क्या बनाता है?

- **सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध:** भारत और नेपाल सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हैं, जिन्हें अक्सर "रोटी-बेटी" के रिश्ते के रूप में वर्णित किया जाता है।
 - पशुपतिनाथ और लुंबिनी जैसे साझा विरासत स्थल इन संबंधों को मजबूत करते हैं।
- **रणनीतिक भौगोलिक महत्व:** नेपाल भारत की सबसे संवेदनशील उत्तरी सीमा के साथ भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के रूप में स्थित है, जिसकी सीमा पांच भारतीय राज्यों से लगती है, जिससे इसकी आंतरिक स्थिरता प्रत्यक्ष रूप से भारत की सुरक्षा चिंता का विषय बन जाती है।
- **मजबूत आर्थिक अन्योन्याश्रितता (Economic Interdependence):** भारत नेपाल के 64% से अधिक विदेशी व्यापार को संचालित करता है और ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और पारगमन पहुँच (transit access) के लिए इसकी प्राथमिक जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है।
- **खुली सीमा:** 1,700 किमी की खुली सीमा लाखों लोगों के लिए वीजा-मुक्त आवाजाही और दैनिक सीमा पार आजीविका को सक्षम बनाती है।
- **जन-से-जन संपर्क:** लगभग 8 लाख नेपाली नागरिक भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट में सेवा दे रहे हैं, जो एक ऐसा सैन्य बंधन है जिसका किसी अन्य द्विपक्षीय संबंध में कोई समानांतर विकल्प नहीं है।

द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?

- **ऊर्जा साझेदारी:** भारत ने 10,000 मेगावाट तक नेपाली जलविद्युत खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, जो नेपाल के जल संसाधनों को साझा समृद्धि के इंजन में बदल रहा है।
 - उदा., अरुण-III और अपर कर्णाली जैसी परियोजनाएं।
- **कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा:** सड़क, पुल, सीमा-पार रेलवे और एकीकृत चेक पोस्ट सहित भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
 - उदा., मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारत की पहली सीमा-पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, नेपाल के हृदय स्थल में सीधे ईंधन की आपूर्ति करती है।
- **डिजिटल और वित्तीय एकीकरण:** भारत ने नेपाल में UPI-आधारित सीमा-पार QR भुगतान का विस्तार किया है, जो औपचारिक व्यापार आंकड़ों से कहीं आगे दैनिक आर्थिक एकीकरण को गहरा कर रहा है।
 - उदा., RBI के 2025 के सुधार जो भारतीय बैंकों को नेपाली संस्थाओं को INR (रुपये) में ऋण देने की अनुमति देते हैं।

- **रक्षा और आपदा सहयोग:** संयुक्त सैन्य अभ्यास और संकटों में पहले प्रतिक्रियाकर्ता (first responder) के रूप में भारत की निरंतर भूमिका भारत को नेपाल के सबसे विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करती है।
 - उदा., अभ्यास सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है; नेपाल के विनाशकारी 2015 के भूकंप के दौरान भारत ने राहत कार्यों का नेतृत्व किया।

संबंधों में तनाव पैदा करने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

- **सीमा विवाद:** कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर ऐतिहासिक संधियों की परस्पर विरोधी व्याख्याएं, साथ ही नेपाल में उनका राजनीतिक महत्व, द्विपक्षीय संबंधों में बाधा बनी हुई हैं।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** 2015 के व्यापार व्यवधान के बाद, नेपाल 2017 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल हो गया।
 - पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं नेपाल के भीतर चीन को एक स्पष्ट रणनीतिक उपस्थिति देती हैं, जो सीधे भारत की पारंपरिक प्रधानता को चुनौती देती हैं।
- **नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता:** सरकार में बार-बार होने वाले बदलाव अक्सर नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव का कारण बनते हैं, जिससे दीर्घकालिक सहयोग और समझौतों का कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है।
- **एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भारत-विरोधी राष्ट्रवाद:** 2015 का सीमा व्यवधान और 2020 का मानचित्र विवाद जैसे मुद्दे जनमत को प्रभावित करते रहते हैं और कभी-कभी घरेलू राजनीतिक लामबंदी के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- **खुली सीमा की सुरक्षा कमजोरियां:** जहाँ एक ओर खुली सीमा एक प्रमुख ताकत है, वहीं दूसरी ओर यह तस्करी, अवैध प्रवास और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों से संबंधित चुनौतियाँ भी पैदा करती है।

वर्तमान कूटनीतिक चरण एक अनूठा अवसर क्यों प्रस्तुत करता है?

- **व्यावहारिक नेतृत्व का उदय:** नेपाल का युवा, विकासोन्मुखी नेतृत्व ऐतिहासिक विवादों की तुलना में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग पर अधिक केंद्रित प्रतीत होता है, जो रचनात्मक जुड़ाव के लिए जगह बनाता है।
- **नए सिरे से उच्च स्तरीय जुड़ाव:** 2025-26 के दौरान वरिष्ठ नेपाली नेताओं की द्विपक्षीय यात्राओं की श्रृंखला विश्वास को फिर से बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर:** हितों का वर्तमान अभिसरण भारत को नेपाल की अस्थिर घरेलू राजनीति द्वारा कूटनीतिक माहौल को संभावित रूप से बदलने से पहले संबंधों को मजबूत करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।

आगे की राह क्या है?

- **समयबद्ध द्विपक्षीय सीमा समाधान:** बाहरी संलिप्तता के बिना लंबित सीमा मुद्दों को हल करने के लिए तकनीकी और कार्टोग्राफिक (मानचित्रण) विशेषज्ञता द्वारा समर्थित एक समयबद्ध द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- **भारतीय सेना-नेपाल सेना के संबंधों का लाभ उठाएं:** भारतीय और नेपाली सेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संस्थागत संबंधों को व्यावहारिक सीमा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बैकचैनल के रूप में औपचारिक रूप से सक्रिय किया जाना चाहिए।
- **ऊर्जा साझेदारी को फास्ट-ट्रैक करें:** जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली व्यापार में तेजी लाने से स्थिरता और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकता है।

- **1950 की संधि रूपरेखा का आधुनिकीकरण:** समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए शांति और मित्रता की संधि (Treaty of Peace and Friendship) का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, जो अधिक पारस्परिकता (reciprocity), संप्रभु समानता (sovereign equality) और पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करे।
- **नेपाल को एक संरक्षित राज्य (Protectorate) के बजाय एक भागीदार के रूप में मानें:** भारत को नेपाल के साथ एक समान रणनीतिक भागीदार के रूप में जुड़ना चाहिए, और केवल ऐतिहासिक लाभों पर निर्भर रहने के बजाय कनेक्टिविटी, निवेश और विकास सहयोग के माध्यम से अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहिए।

